भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 199
उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में डिजिटल अवसंरचना

†199. श्री अमरसिंग टिस्सो:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में कितने सरकारी विद्यालय समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्मार्ट क्लासरूम, आईसीटी लैब और इंटरनेट सुविधाओं जैसी डिजिटल अवसंरचना से सुसज्जित हैं;
(ख) क्या सरकार ने कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जैसे आदिवासी और पहाड़ी जिलों में अवसंरचना संबंधी अन्तर की पहचान की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) ऐसे शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल पहुँच में सुधार हेतु कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। असम राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, कुल लक्षित 10,689 स्कूलों में से 9,240 सरकारी/प्रांतीयकृत उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को आईसीटी और स्मार्ट कक्षाओं के अंतर्गत लाया जा चुका है। सभी आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं में इंटरनेट सुविधाएँ प्रदान की गई हैं और जिन स्कूलों में टेली-एजुकेशन लागू है, वहाँ वीसैट कनेक्टिविटी स्थापित की गई है।

(ख) और (ग): असम सरकार ने आदिवासी और पहाड़ी जिलों, विशेष रूप से दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग और पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिलों में मूलभूत अवसंरचना की कमी की पहचान की है और इन जिलों के स्कूलों में डिजिटल सुविधाएँ प्रदान की हैं। राज्य सरकार असम के सभी जिलों, जिनमें आदिवासी और पहाड़ी जिले भी शामिल हैं, को चरणबद्ध तरीके से सभी संभव नए युग की शिक्षण पद्धतियां प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो और स्कूलों में डिजिटल विभाजन को कम किया जा सके।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की डिजिटल पहल, विशेष रूप से "आईसीटी और स्मार्ट क्लासरूम घटक", विद्यार्थियों को मूलभूत अवसंरचना प्रदान करती है और कक्षा को तकनीक-संचालित कक्षा में बदल देती है। विद्यार्थी मल्टीमीडिया सामग्री और इंटरैक्टिव गतिविधियों में अधिक संलग्न होते हैं, साथ ही संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुँच प्राप्त करते हैं। इससे विद्यार्थियों में गहरी समझ, सहयोग और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिलता है, जिससे उनका समग्र शैक्षिक अनुभव समृद्ध होता है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करने की योजना का उल्लेख किया गया है।

******